

सरकार विरोधी मोर्चा की संभावना

प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की विपक्षी नेताओं से मुलाकात के कारण चुनाव पूर्व सरकार विरोधी मोर्चा की संभावना को बल मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इससे आंध्र प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन और कांग्रेस के अन्य दलों के साथ आने का रास्ता निकल सकता है। राहुल से मुलाकात के पहले नायडू मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, फारु क अब्दुल्ला से मिल चुके हैं। इस तरह वे एक कड़ी की भूमिका में इस समय दिख रहे हैं। राहुल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग पुरानी बातों को भूलकर देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ काम करेंगे। हालांकि राहुल की बातों में नया कुछ नहीं था, लेकिन मिलने और साथ आकर मीडिया से बात करने के कारण गोलबंदी का एक वातावरण बनते हुए तो दिखता ही है। बाद में अब्दुल्ला और पवार के साथ पत्रकारों से बातें करते हुए भी उसी पर जोर दिया गया। पवार ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तक की बात कह दी। मीडिया से हुई इन दोनों बातों से यह तो साफहो गया कि ये सरकार के विरु ढ्ढ प्रमुख संस्थाओं की आजादी पर हमला कर लोकतंत्र को नष्ट करने और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। नायडू ने “सेव नेशन सेव डेमोक्रेसी” का नारा भी दिया। जैसा पवार ने कहा कि योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इन मुलाकातों के दौर खत्म होने के बाद नायडू इन नेताओं को एक साथ बिटाएंगे। जितने नेता एक साथ आएंगे उनसे ये यह दावा कर सकेंगे कि हम मोदी सरकार एवं भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं और गठबंधन की दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी इन कवायदों से बड़ा निष्कर्ष निकाल लेना जल्दबाजी होगा। सभी राज्यों और वहां के प्रमुख दलों की अपनी सियासी आकांक्षाएं और जमीनी वास्तविकाओं की किसी भी गठबंधन में प्रमुख भूमिका होती है। बावजूद इसके इन कवायदों के संभावित राजनीतिक प्रभावों को खारिज नहीं किया जा सकता है। चुनाव पूर्व गठबंधन में जितनी सफलता मिलेगी वह अपनी जगह है ही। अगर परिणाम बाद ऐसी स्थिति आई, जिसमें भाजपा या राजग को बहुमत नहीं मिला तब चंद्रबाबू नायडू की केंद्रीय भूमिका के कारण एक मोर्चा बन सकता है।

सूचना प्रशासन

जम्मू संभाग के किश्तवार इलाके में भाजपा के प्रदेश सचिव एवं उनके भाई की आतंकवादियों द्वारा हत्या ने एक साथ कई भयानक संकेत दिए हैं। इस आतंकवादी वारदात का आरोप लश्कर-ए-तैयबा पर लगाया गया है। किश्तवार के इलाकों में काफी समय से कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। इस हमले का अर्थ है कि आतंकवादी उस क्षेत्र में आ चुके हैं। आगामी 19 नवम्बर के पंचायत चुनाव को देखते हुए वहां और भी हमले की योजना वे बना रह होंगे। पहला संकेत तो यही है कि आतंकवादी पंचायत चुनाव को हर हाल में विफल करना चाहते हैं। इसके पहले नगर निकायों के चुनावों में पूरे जम्मू संभाग में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उसमें भाजपा को काफी सफलता मिली। यह बिल्कुल संभव कि प्रदेश के एक बड़े भाजपा नेता का अंत कर वे भाजपा समर्थकों के साथ मतदाताओं को भी भयभीत करना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश सचिव अनिल परिहार इसके पूर्व स्थानीय चुनावों में काफी सक्रिय थे। घाटी में भी पार्टी ने उनको भेजा था। वहां भी चुनाव में उन्होंने काम किया था। इस कारण भी आतंकवादियों की उन पर नजर रही होगी। जैसा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कुछ दिनों पहले खुफिया के एक अधिकारी उनसे मिलने आए थे, जिन्होंने बताया था कि आतंकवादी भाजपा के नेताओं को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। यह सूचना प्रशासन को बिल्कुल रही होगी। इस समय प्रदेश राज्यपाल शासन में है इसलिए राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति नहीं है। किंतु किसी भी स्थिति में आतंकवादियों के इरादों को सफल न होने देना ही इसका करारा प्रत्युत्तर है। पंचायत चुनावों में भारी संख्या में मतदान कर उनको जताया जा सकता है कि आतंकवादी हमलों से डरकर लोग पीछे नहीं हटने वाले। सुरक्षा की जितनी संभव व्यवस्था हो की जानी चाहिए ताकि लोग निर्भय होकर मतदान कर सकें। बावजूद इसके यह घटना बताती है कि आतंकवाद के संघर्ष में अभी अनेक लोगों को अपने या परिजनों की बलि चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। यही जज्बा आतंकवाद को परास्त करेगा। आतंकवादियों को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वे अपनी बंदूकों के बल पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोटने के अपने गंदे लक्ष्यों में सफल नहीं हो सकते।

सत्संग

मन

कल्पना कामना नहीं है, मात्र एक खेल है। कामना तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन तुम अपनी कल्पना को कामना पर आधारित कर सकते हो, तुम अपनी कामना को कल्पना द्वारा प्रक्षेपित कर सकते हो, तब वह बंधन हो जाएगी। यदि तुम कल्पना के साथ बिना किसी कामना के खेलते हो-न कहीं पहुंचने के लिए, न कुछ पाने के लिए, बस एक खेल की तरह उसे लेते हो-तब तुम्हारी कल्पना न कामना होती है, न बंधन। कल्पना की ये विधियां केवल तभी सहयोगी हो सकती हैं यदि तुम उनके साथ खेलो। यदि तुम गंभीर हो गए तो सारी बात ही चूक गए। लेकिन प्रश्न संगत है। क्योंकि वास्तव में, तुम सोच ही नहीं सकते कि बिना कामना के कुछ किया जा सकता है। तुम तो अगर खेलते भी हो तो कहीं पहुंचने के लिए, कुछ पाने के लिए, जीतने के लिए। यदि भविष्य में कुछ भी मिलने वाला न हो तो तुम्हारा सारा रस खो जाएगा। तुम कहोगे, “फिर खेलें ही क्यों?” हम इतने परिणाम-उन्मुख हैं कि हर चीज को साधन बना लेते हैं। इसे स्मरण रखना चाहिए: ध्यान तो परम लीला है, कुछ पाने के लिए, साधन नहीं है, ध्यान बुद्धत्व पाने के लिए साधन नहीं है। ध्यान से बुद्धत्व घटता है, लेकिन ध्यान उसके लिए साधन नहीं है। न ही ध्यान मोक्ष के लिए साधन है। मोक्ष उससे घटता है, लेकिन ध्यान उस के लिए साधन नहीं है। तुम ध्यान का किसी फल की प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं कर सकते। यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिन्होंने भी जाना है, वे सदियों से ध्यान के लिए ही ध्यान करने पर जोर देते रहे हैं। उससे कुछ पाने की कामना मत करो, उसका आनंद लो, उससे बाहर कोई लक्ष्य मत बनाओ-और बुद्धत्व उसका परिणाम होगा। स्मरण रखो, परिणाम, फल नहीं। ध्यान कोई कारण नहीं है, लेकिन ध्यान में तुम गहरे डूबते हो तो बुद्धत्व घट जाता है। असल में, इस खेल में गहरे डूब जाना ही बुद्धत्व है। लेकिन मन हर चीज को कार्य बना लेता है। मन कहता है, कुछ करो क्योंकि उससे यह लाभ होगा। काल्पनिक या वास्तविक, मन को कुछ चाहिए जिससे सहारा मिल सके, जिसे मन प्रक्षेपित कर सके। केवल तभी मन चल सकता है। मन भविष्य के लिए वर्तमान में काम करता है। भविष्य चाहे काल्पनिक ही हो, चाहे कभी आए ही न, लेकिन मन केवल भविष्य की आशा में ही काम कर सकता है। भविष्य के लिए वर्तमान में काम करने को ही कामना कहते हैं।

‘‘माउंटबेटेन प्लान’’

कश्मीर के महाराजा, हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब द्वारा अब तक किसी भी संघ में विलय नहीं किया गया था। हरि सिंह द्वारा अब तक भारत में शामिल नहीं होने के निर्णय से आशंका यह भी बन रही थी कि वह पाकिस्तान में भी विलय चाहते हैं। प्रांतीय सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ ``स्टैंड स्टील एग्रीमेंट´ के बाद ऐसे कयास और तेज होने लगे थे। ब्रिटिश भारतीय शासन द्वारा तैयार किए गए इस एग्रीमेंट के तहत रियासतों द्वारा किसी भी संघ में विलय की अवधि तक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हूबहू लागू रखने का प्रावधान था, जिसे भारत ने ठुकरा दिया और पाकिस्तान ने बिना कोई देरी किए स्वीकार कर लिया।

सतीश पेडणोकर

1947 में भारत से अंग्रेजों की विदाई के साथ ही रियासतों के समक्ष भारत या पाकिस्तान में विलय संबंधी निर्णय लेने की चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। 3 जून 1947 को घोषित “‘माउंटबेटेन प्लान’ के तहत स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश स्वामित्व समाप्त होकर इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल होना होगा। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत और भावी पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 तक सत्ता हस्तान्तरित करने के लिए “इंडियन इंडीपेंडेंस एक्ट’ के तहत रियासतों की विलय प्रक्रिया शुरू हुई। 15 अगस्त तक अधिकांश राजाओं द्वारा भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन कुछ राजा पाकिस्तान में शामिल होने का मंसूबा पाले बैठे थे। कश्मीर के महाराजा, हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब द्वारा अब तक किसी भी संघ में विलय नहीं किया गया था। हरि सिंह द्वारा अब तक भारत में शामिल नहीं होने के निर्णय से आशंका यह भी बन रही थी कि वह पाकिस्तान में भी विलय चाहते हों। प्रांतीय सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ “स्टैंड स्टील एग्रीमेंट’ के बाद ऐसे कयास और तेज होने लगे थे। ब्रिटिश भारतीय शासन द्वारा तैयार किए गए इस एग्रीमेंट के तहत रियासतों द्वारा किसी भी संघ में विलय की अवधि तक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हबहू लागू रखने का प्रावधान था, जिसे भारत ने ठुकरा दिया और पाकिस्तान ने बिना कोई देरी किए स्वीकार कर लिया। भौगोलिक-आर्थिक कारणों से भी कश्मीर का पाकिस्तान में मिलने की संभावनाएं चिंताएं बढ़ा रही थीं। निश्चित ही कश्मीर के अहम भौगोलिक संचार माध्यम और आर्थिकी संपर्क पश्चिमी पंजाब और उत्तर-पश्चिम के सीमांत राज्यों से जुड़े थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में थे। उस समय की एकमात्र रेल लाइन जो जम्मू-कश्मीर को जोड़ती थी, उत्तर-पश्चिम रेलवे की ही लिंक लाइन थी। पाकिस्तान में विलय की घोषणा में देरी के कारण कश्मीर को पेट्रोल, गेहूं और नमक जैसी आवश्यक सामग्री की आपूर्त् में बाधा भी झेलनी पड़ी। ऐसे तमाम हथकंडों से पाकिस्तान दबाव बनाकर कश्मीर को अपने में शामिल कराने का हरसंभव प्रयास करता रहा। हरि सिंह के दुलमुल रवैये से भी पाक के मंसूबों को बल मिलता रहा। अंततः 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों द्वारा जम्मू-कश्मीर पर किए गए हमले से अपनी और राज्य के बचाव के मद्देनजर राजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में कश्मीर के विलय की घोषणा कर दी। इसी सुबह पहले सिख रेजीमेंट के लगभग 300 सैनिकों द्वारा श्रीनगर पहुंचकर पाकिस्तानी घुसपैठियों पर काबू पाने की तेज कार्रवाई कर हवाई अड्डा परिसर को अपने कब्जे में किया गया। इस लड़ाई में स्वयं कश्मीरी भी पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुकाबला कर रहे थे। कहा जाता है कि एक

घंटे की देरी भी भारतीय सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी। विभाजन की आग में कई जगहों पर धर्म आधारित हिंसक घटनाएं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रही थीं। महत्त्वपूर्ण है कि आज सात दशक बाद भी कश्मीर-विवाद एक ज्वलंत विषय बना हुआ है। इस स्थिति में बड़ा सवाल है कि इस विवाद का निपटारा अब तक क्यों नहीं हो पाया? अलगाववाद, उग्रवाद और अब आतंकवाद की चपेट में कश्मीर क्यों झुलस रहा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब में ऐतिहासिक तयों की भूमिका अहम है। 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों द्वारा जम्मू-कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को लगभग 70 लाख नानकशाही रूप में बेच दिया गया था, जिसका तत्कालीन गवर्नर शेख इमामुद्दीन द्वारा विरोध भी हुआ था। अमुत्तर संधि के तहत जम्मू-कश्मीर पर गुलाब सिंह के स्वामित्व और संधि की राजनीतिक-नैतिक स्थितियों को कश्मीरी नेताओं द्वारा कई अवसरों पर चुनौती भी मिलती रही है। उनके अनुसार इस संधि में कश्मीरियों को पार्टी नहीं बनाया जाना असंतोष की जड़ बनी। सन् 1925 में हरि सिंह कश्मीर के राजा बने। दूसरी ओर 1932 में शेख अब्दुल्ला ने “मुस्लिम कॉंग्रेस’ की स्थापना कर अधीनस्थ मुसलमानों के अधिकारों के हिमायती के रूप में घाटी से प्रांतीय शासन समाप्त करने का मोर्चा संभाल लिया था। गांधीजी के आह्वान पर शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉंग्रेस को नेशनल कॉंग्रेस बनाकर इसे न केवल मुस्लिम हिमायत की पहचान तक सीमित रखा बल्कि प्रांतीय शासकों के खिलाफउनकी लड़ाई में राज्य हित के मुद्दे भी शामिल किया। पंडित नेहरू से करीबी के बाद शेख की राजनीति पहले से ज्यादा मुखर हो गई। 1946 में अब्दुल्ला ने “कश्मीर-छोड़ो’ आंदोलन से शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। शेख के प्रति नेहरू की संवेदनशीलता का अंदाजा इस घटना से भी लगाया जा सकता है



कि जून 1946 में उन्हें रिहा कराने के लिए नेहरू ने कश्मीर जाने की घोषणा कर दी थी। कुल मिलाकर, भारत की धर्मनिरपेक्षता, कश्मीरियत में नेहरू और शेख अब्दुल्ला का विश्वास और अंदतः हरि सिंह की मजबूरी के बीच जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का अंग बन गया। अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संसद को सिर्फरक्षा, विदेश मामले और संचार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त रहा है। इसकी आत्मा कही जाने वाली धारा 35ए वहां के नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। मसले की नाजुकता के बावजूद आए दिन धारा 370 को समाप्त करने की राजनीतिक क्वालत होती रही है। देश के एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान प्रशंसनीय हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन की प्रस्तावित योजना के तहत पूरा बंगाल, पंजाब और असम पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा था। दूरदर्शी पटेल ने

प्रस्तावना का कड़े शब्दों में विरोध करते हुए कहा, “यह प्रस्ताव तो पाकिस्तान बनाने के प्रस्ताव से भी ज्यादा खराब है।” बाद में एक बन फिर से 20 फ़रवरी 1947 को एटली नीति के तहत पंजाब, बंगाल और असम जिन्ना के खाते में डाले जाने का प्रस्ताव रखा गया। दोबारा लाए गए इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकराते हुए पटेल ने पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पेश कर दिया और पूरा असम भारत का हिस्सा बना। सच भी है कि यदि राजा 15 अगस्त 1947 को अपनी हठधर्मिता त्यागकर भारत में विलय कर दिया होता तो समस्या पैदा ही नहीं होती। निःसंदेह, कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने जैसी कवायद पंडित नेहरू की बड़ी चूक थी। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष की जयंती पर उनका स्मरण राष्ट्रीय एकता के संकल्पों की याद दिलाता है।

पीड़ितों को “इंसाफ

शिमपुरा नरसंहार मामले में पीड़ितों को आखिरकार “इंसाफ़ मिल गया है। इस नृशंस नरसंहार के गुनहगारों को इकतीस साल बाद ही सही अपने किए की सजा मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस चर्चित मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए प्रोविंशियल आर्माड कॉन्स्टेबुलरी यानी पीएसो के 16 रिटायर जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने पीएसो के जवानों को हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया। अदालत का इस बारे में कहना था कि सभी के खिलाफ मजबूत ठोस सबूत हैं। यह सीधे-सीधे हिरासत में मौत का मामला है। इस मामले में पीएसी जवानों ने मानवाधिकार का हनन किया है। न्यायपालिका से संबंधित प्रचलित धारणा है कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं कहलाता। फिर इस मामले में, तो इंसाफ़ मिलने में पूरे इकतीस साल लगे। इस दौरान नरसंहार के तीन मुजरिम, बिना सजा पाए अपनी मौत मर गए। वहीं पीड़ितों ने इंसाफ़ पाने के लिए क्या-क्या नहीं झेला। पीड़ित तमाम दबाव झेलते रहे, लेकिन अपने इरादे से नहीं डिगे। अदालत के इस फैसले से पीड़ितों के अपने वापस तो नहीं आ सकेंगे, पर उनके जख्मों पर कुछ मरहम जरूर लगेगा। बर्दी की आड़ में जो लोग, मजलूमों पर जुल्म-ओ-सितम ढाते हैं, उन्हें डर रहेगा कि यदि उन्होंने कुछ गलत किया, तो कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा। कभी-न-कभी उन्हें अपने किये की सजा जरूर मिलेगी। “हाशिमपुरा नरसंहार’ नाम से पहचाने जाने वाला यह दर्दनाक मामला, साल 1987 के 22–23 मई की दरमियानी रात का है। उस वक़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका साम्प्रदायिक दंगों में झुलस रहा था। मेरठ जिले के हाशिमपुरा गांव में अचानक पीएसो के जवान आए और एक सभा से अल्पसंख्यक समुदाय के 42 से 45 नौजवानों को टूक में भरकर अपने साथ ले गए। बाद में पीएसो के जवानों ने टूक में सवार लोगों को मुरादनगर गंगनहर पर ले गए और उन्हें गोलियों से भून दिया। बाद में उनकी लाशों को नहर में फेंक दिया। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह बहुत तकलीफ़देह है कि कुछ बेगुनाह लोगों को इतनी यंतप्रा झेलनी पड़ी और एक सरकारी एजेंसी ने उनकी जानें लीं। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने अप्सोस भर लहजे में कहा, जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष दोषियों की पहचान को साबित करने लायक सबूत पेश करने में नाकाम रहा। लिहाजा मौजूदा परिस्थितियों में सभी 16 अभियुक्तों को उन पर लगाए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। निचली अदालत द्वारा हत्या और अन्य अपराधों के आरोपित 16 पूर्व पुलिसकर्मियों को बरी करने के फैसले से पीड़ित परिवार, जरा सी भी हिम्मत नहीं हारे। पीड़ित परिवारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार और दीगर लोगों ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जहां अदालत ने आखिरकार पीड़ितों के हक में इंसाफ़ सुनाया। हाशिमपुरा मामले में गुनहगार खुद पुलिस थी, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने ही अपने मातहतों को बचाने का काम किया। इस मामले के ज्यादातर सबूतों को दबाया गया या नष्ट कर दिया गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभियुक्त पुलिसवालों को कभी भी निर्लिखित नहीं किया गया। होना तो यह चाहिए कि जो इस अपराध के सहभागी या आपराधिक लापरवाही के दोषी हैं, उनकी भी इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाए और उन्हें उनके किए की उचित सजा मिले। तभी इस मामले में पीड़ितों को सही इंसाफ़ मिलेगा।

सार समाचार

काबुल में हमले में अमेरिकी सैनिक की मौत : नाटो

काबुल। काबुल में वस्तुतः ‘‘वस्तुतः दोस्त का भेष धरे दुश्मन’’ के हमले में अमेरिका का एक सैनिक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। नाटो ने कहा है कि अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय बलों पर इस तरह का यह ताजा हमला है। नाटो के ‘रिजाल्यूट सपोर्ट मिशन’ ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि हमलावर ‘अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल’ (एएनडीएसएफ) का एक सदस्य था।’’ इसमें बताया गया है कि अन्य अफगान सैनिकों ने हमलावर को मार गिराया। घायल सैनिक को अफगान राजधानी के उत्तर में स्थित बगराम हवाई अड्डा ले जाया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उसकी हालत स्थिर है। बयान में बताया गया है कि घटना की जांच की जा रही है। मारे गये सैनिक की पहचान तत्काल उजागर नहीं की गई है।

अर्जेंटीना में नयी सारापोड प्रजाति के डायनासोर की खोज

ब्यून्स आयर्स। स्पेन और अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों के करीब 11 करोड़ वर्ष पहले देश के मध्य में निवास करने वाले डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है। इसमें तीन अलग अलग डायनासोर के जीवाश्म मिले है जो सारापोडस के शाकाहारी समूह की प्रजातियों से संबंधित हैं। इन्हें डिल्टोडोक्स और ब्रॉटोसॉरस के तौर पर बेहतर तरीके से जाना जाता है। नयी प्रजाति को लावाकाटिसोरस एग्रीओनसीस का नाम दिया गया है। अर्जेंटीना के एंजिडिओ फेरुगिलिओ संग्रहालय और राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध परिषद के शोधकर्ता जोस लुइस कार्बालिडो ने शुरुवार को बताया, ‘‘हमें सबसे अधिक हड्डियां मिली जिसमें नाक के आगे का हिस्सा, जबड़े, बहुत दांत, आंखों के कोटरों के साथ गर्दन, पूंछ और पीठ के हिस्से भी पाये गये। इस तरह से पूरी ढांचे को फिर से बनाने में सक्षम हैं।’’ जीवाश्म वैज्ञानिकों ने बताया कि व्यस्क डायनासोर का जीवाश्म करीब 12 मीटर लंबा रहा होगा और दो कम उम्र के डायनासोर छह से सात मीटर के होंगे। ये सभी डायनासोर एक समूह में रहते थे और एक साथ मारे गये होंगे। स्पेन की जागोजा विश्वविद्यालय के जोस इग्नासिओ कनुडो की अगुवाई में किए गए अध्ययन में कहा गया, एक व्यस्क और दो कम उम्र के डायनासोर के समूह विस्थापन के पहले रिकॉर्ड को भी दर्शाती है।

ईरान के साथ नया समझौता करने के लिए तैयार हैं: ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ एक नए व्यापक समझौते के लिए तैयार हैं लेकिन तब तक पश्चिम एशियाई देश पर सोमवार से शुरू हो रहे सख्त प्रतिबंध जारी रहेंगे। ट्रंप ने शुरुवार देर रात एक बयान में कहा, ‘‘अमेरिका, ईरान के साथ नया, और अधिक व्यापक समझौता करने के लिए तैयार है जो हमेशा के लिए परमाणु हथियार का उसका रास्ता रोक देगा, उसकी दुर्भावनापूर्ण हरकतों पर लगाम लगाएगा और ईरान के लोगों के लिए उपयुक्त होगा।’’

नकदी संकट में फंसे पाकिस्तान को चीन देगा ‘जरूरी मदद’

बीजिंग (एजेंसी)।

पाकिस्तान को वर्तमान आर्थिक संकट से उबारने के लिए चीन उसे ‘जरूरी मदद’ उपलब्ध कराएगा। एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह बात कही। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीने प्रधानमंत्री ली क्जिंग से मुलाकात की और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। इसके बाद दोनों देशों ने 16 करार पर हस्ताक्षर किये। खान अपनी पहली चीन यात्रा पर शुरुवार को यहां पहुंचे। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच कई अरब डॉलर के सीपीईसी को लेकर मतभेदों को दूर करना है। इसके अलावा वह ‘मित्र देशों’ से संपर्क कर रहा है ताकि उसे कड़े शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से राहत राशि नहीं लेनी पड़े।

हाखान का स्वागत करते हुए क्जिंग ने कहा, ‘‘आप कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान हर वक के साझीदार हैं।’’ क्जिंग ने कहा, ‘‘हमारे बीच बहुत अधिक राजनीतिक विश्वास है और सभी क्षेत्रों में करीबी सहयोग संबंध है। चीन अपनी विदेश नीति के तहत हमेशा से पाकिस्तान को प्राथमिकता देता आया है। आपकी यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।’’ क्जिंग को धन्यवाद देते हुए खान ने कहा, ‘‘2013 में सीपीईसी केवल एक विचार था और तब से अब तक दोनों देशों के रिश्ते में अधिक गहराई आयी है। अब यह जमीन पर उतर चुका है। पाकिस्तान के लोगों को यह परिकल्पना पसंद आयी है।’’ खान ने कहा कि उनका देश चीन में प्रगति और निवेश को आमंत्रित करने के अवसर देखाता है।



एमजे अकबर की सफाई पर पल्लवी ने दिया जवाब, ‘जबर्दस्ती और खौफ का रिश्ता सहमति का नहीं होता’

नई दिल्ली (एजेंसी)।

अपनी सहयोगी महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप झेल रहे एमजे अकबर को उनकी पुरानी सहयोगी ने उस बयान के लिए लताड़ लगाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच आपसी सहमति से रिश्ते थे. पल्लवी ने कहा, मैं अपने हर उस शब्द के साथ दृढ़ता से खड़ी हूँ, जिसे मैंने पहले कहा था. अमेरिका में नेशनल पब्लिक रेडियो की चीफ बिजनेस एडिटर पल्लवी गोगोई ने अकबर पर जयपुर में रैप करने का आरोप लगाया था. जिस एमजे अकबर ने सहमति के रिश्ते बताकर खारिज किया था. पल्लवी ने ये आरोप ‘वाशिंगटन पोस्ट’ में एक लेख में लगाए थे.

पल्लवी अकबर के साथ ‘द एशियन एज’ में काम कर चुकी हैं. अकबर के खिलाफ करीब 20 महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था. लेकिन



पल्लवी के साथ रिश्ते उन्होंने स्वीकारे थे, था. लेकिन अब पल्लवी ने उनके इन आरोपों उनका कहना था कि ये सब कुछ सहमति से को भी खारिज कर दिया है. पल्लवी का

कहना है कि उन्होंने अपनी पीड़ा के बारे में ये लेख अपनी बेटी और बेटे के लिए लिखा है. ताकि कभी उनके सामने ऐसे हालात आएँ तो वह मुकाबला कर सकें. पल्लवी का कहना है कि उनका ये लेख ऐसे लोगों को भी सच बोलने के लिए प्रेरित करेगा, जो इस तरह के हालात से गुजरे हैं.

अकबर ने शुरुवार को कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे. यहां तक कि अकबर की पत्नी ने गोगोई पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. गोगोई ने अकबर के बयानों को खारिज करते हुए टवीट कर कहा मेरे साथ गलत हरकत करने और अन्य युवा महिलाओं को अपना शिकार बनाने की जिम्मेदारी लेने के बजाए अकबर कह रहे हैं कि संबंध सहमति से बने थे. ऐसा नहीं था. पल्लवी ने अकबर पर निशाना साधते हुए कहा, एक ऐसा रिश्ता जो खौफ पैदा कर सता का गलत इस्तेमाल कर बनाया जाए तो वह सहमति से बना रिश्ता नहीं होता है.

पाकिस्तान: ‘तालिबान के गॉडफादर’ का किया गया अंतिम संस्कार, चाकू घोंपकर की गई थी हत्या



इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान में शीर्ष तालिबान समर्थक धर्मगुरु मौलाना समीउल हक को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अकांझा खड्क नगर स्थित मदरसा दारुल उलूम हकानिया में शनिवार को

सुपुर्दे खाक कर दिया गया. 82 वर्षीय धर्मगुरु को ‘‘तालिबान के गॉडफादर’’ के तौर पर भी जाना जाता था. अज्ञात हमलावरों ने गत शुरुवार को रावलपिंडी शहर स्थित उनके आवास पर धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी थी. हक के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए जिसमें नेशनल असैम्बली के स्पीकर असद कैसर, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गवर्नर शाह फरमान, मुख्यमंत्री महमूद खान शामिल थे.

जनाजे की नमाज उनके पुत्र मौलाना हामिदुल हक ने पढ़ाई. जनाजे की नमाज के बाद हक को दारुल उलूम हकानिया में उनके पिता की कब्र के बगल में दफना दिया गया. हक के अंतिम संस्कार में राजनीतिक दलों के सदस्य, धार्मिक विद्वान और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. इसमें 65 सदस्यीय अफगान प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ.

पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए दारुल उलूम हकानिया और उसके आसपास स्थित विभिन्न स्थलों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. हक दारुल उलूम हकानिया के प्रमुख थे. दारुल उलूम हकानिया को पश्चिमी मीडिया द्वारा ‘‘जिहाद का विश्वविद्यालय’’ कहा जाता है क्योंकि वहां पर अफगान और पाकिस्तानी तालिबान के कई नेताओं ने शिक्षा ग्रहण की है. उनमें मुल्ल उमर भी शामिल है जिसे इस मदरसे ने डाक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी. हक धार्मिक-राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख भी थे जो कि सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सहयोगी है . पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री इमरान खान करते हैं. हक दो बार संसद के सदस्य भी रहे. अभी तक किसी भी संगठन ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है. पुलिस ने कहा कि हमलावरों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर

दिया गया है जो संभवतः बाइक पर फरार हुए थे. एयरपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करायी गई एक प्राथमिकी में कहा गया है कि हमला शाम पौने सात बजे हुआ और हक के पेट, सीने, माथे और कान पर 12 बार वार किए गए. प्राथमिकी हक के पुत्र हामिदुल हक की शिकायत पर दर्ज की गई जिन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पिता हमले के समय अकेले थे. पुत्र ने हक का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और इसे इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ बताया. इस बीच पुलिस ने हक के चालक और सुरक्षाकर्मी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.रावलपिंडी पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल किया है. सूत्रों ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या में कम से कम दो हमलावर शामिल थे.

चीन ने जीपीएस प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक और उपग्रह प्रक्षेपित किया

वाशिंगटन (एजेंसी)।

बीजिंग। चीन ने अमेरिकी ग्लोबल पोजिशन सिस्टम (जीपीएस) की प्रतिस्पर्धा में घरेलू विकसित बीदाऊ ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरुवार को एक और उपग्रह पृथ्वी की उच्च कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। सरकारी नियंत्रण वाले मीडिया शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के दक्षिण-पश्चिम सिचुआन प्रांत में शीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से यह उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसे लांग मार्च-3बी एंटीग्रैव रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया। यह बीदाऊ नेविगेशन प्रणाली का 41 वां उपग्रह है और यह पहले से ही कक्षा में कार्यरत 16 अन्य बीदाऊ -3 उपग्रहों के साथ काम करेगा। यह पृथ्वी के ऊपर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उच्च कक्षा में भेजा गया

पहला बीदाऊ-3 उपग्रह भी है। इस उच्च कक्षा को भूस्थैतिक कक्षा कहा जाता है। इस कक्षा में भेजे गए उपग्रह पृथ्वी से लगातार एक ही बिंदु से दिख सकते हैं। यानी इन पर धरती के घूमने का असर नहीं होता क्योंकि इस दूरी पर उपग्रह और धरती एक ही गति से घूमते हैं। एक समान गति के कारण इस कक्षा के उपग्रह पृथ्वी से स्थिर लगते हैं। रिपोर्ट में प्रणाली के मुख्य डिजायनर यांग चांगफेंग के हवाले से बताया गया है कि चीन के प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) में शामिल देशों की सेवा के लिए वर्ष के अंत तक बीदाऊ-3 उपग्रहों के साथ एक मूल प्रणाली की व्यवस्था काम करने लगेगी। यह वर्ष बीदाऊ उपग्रहों के सघन प्रक्षेपणों के नाम रहा है।

यांग ने कहा कि चीन इस वर्ष के अंत तक अंतरिक्ष में अन्य दो उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेडियो नेविगेशन की अलावा, यह उपग्रह एक बेहतर

रेडियो निर्धारण उपग्रह सेवा से लैस है जो प्रत्येक घंटे एक करोड़ ग्राहकों को लघु संदेश भेज सकता है। बीदाऊ -3 श्रृंखला के मुख्य डिजाइनर पैन युकियन ने कहा, ‘‘यदि कोई नेविगेशन सिमल गलत हो जाता है, तो सैटेलाइट अन्य सिमल पर जाने के लिए उपयोगकर्ताओं को 6 सेकंड के भीतर सूचित कर सकता है।’’उपग्रह पर हाइड्रोजन और रूबिडियम परमाणु घड़ियों को लगाया गया है, जो स्थिति और समय सटीकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। बीदाऊ प्रणाली ने 2000 में चीन और 2012 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सेवाएं देना शुरू कर दिया था। अमेरिकी जीपीएस प्रणाली, रूस की ग्लोनास और यूरोपीय संघ के गैलिलियो के पश्चात यह चौथी वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 2020 तक, जब बीदाऊ प्रणाली वैश्विक हो जायेगी, तो इसमें 30 से अधिक उपग्रह होंगे।



प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो फिर शुरु हो सकता है परमाणु कार्यक्रम- उत्तर कोरिया

सियोल (एजेंसी)।



उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका उसके खिलाफ लगे आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाता है तो वह परमाणु हथियारों को मजबूत करने संबंधी अपनी नीति को फिर से प्रभावी बना सकता है। प्रतिबंधों के प्रयोग और उत्तर कोरिया पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने के दबाव के कारण वाशिंगटन और सियोल के बीच तल्लू की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्रालय की ओर से शुरुवार की शाम यह बयान जारी किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि यदि अमेरिका ने अपना रूख नहीं बदला तो उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए अपनी ‘योगजिन’ नीति को फिर से प्रभावी बना सकता है। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रमों के संबंध में अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को खत्म करने की लाभग धमकी दे डाली है। मंत्रालय के इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडिज के निदेशक के नाम से जारी इस बयान में कहा गया है, ‘‘अमेरिका को लगता है कि बार-बार प्रतिबंध लगाने और दबाव बढ़ाने से परमाणु निस्स्त्रीकरण होगा। हम ऐसे बेवकूफाना विचार पर हंसने से खुद को नहीं रोक पाए।’’ उसका कहना है कि संबंधों में सुधार और प्रतिबंध दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते हैं।

एच1 बी वीजा धोखाधड़ी मामले में भारतीय-अमेरिकी सिलिकॉन वैली से गिरफ्तार

वाशिंगटन (एजेंसी)।

एच-1बी वीजा धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया है। किशोर कुमार कावुरू को शुरुवार सुबह गिरफ्तार कर अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश सुसन वान केउलेन के समक्ष पेश किया गया। बाद में आरोपी को मुचलके पर छोड़ दिया गया। कावुरू पर वीजा धोखाधड़ी के 10 आरोप तथा मेल धोखाधड़ी के भी इतने ही आरोप लगाए गए हैं। यह मामला उसकी कंसल्टिंग कंपनी के उपभोक्ताओं के लिए विदेशी कामगारों का एक समूह तैयार रखने की योजना से जुड़ा हुआ है।

मामले के अनुसार कावुरू 2007 से चार कन्सल्टिंग कंपनियों का मालिक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। उस पर श्रम मंत्रालय तथा गृह सुरक्षा मंत्रालय दोनों के पास फर्जी दस्तावेज जमा कराने के आरोप हैं जिनमें विदेशी कर्मचारियों के लिए फर्जी कार्य परियोजनाओं के व्योरो का जिक्र था। संघीय अभियोजकों ने बताया कि चूंकि इनमें से अधिकतर आवेदन मंजूर हो जाते थे, इसलिए भारतीय अमेरिकी के पास बेरोजगार एच-1 बी लाभार्थियों की अच्छी तादाद थी जो कानूनी कार्य परियोजनाओं के लिए तत्काल उपलब्ध रहते थे। इससे उसे वीजा आवेदन की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने वाली अन्य स्टॉफ कंपनियों के मुकाबले लाभ मिलता था। न्याय मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि योजना के तहत कावुरू को भावी कर्मचारियों की जरूरत थी जो वीजा आवेदनों के तैयार और जमा होने से पहले हजारों डॉलर नकद अदा कर सकें। इसी के साथ उसे ऐसे कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी जिन्हें बिना भुगतान के इंतजार कराया जा सके। कई बार तो उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। अभियोजकों ने कहा कि अपनी कन्सल्टिंग कंपनियों के जरिए कावुरू ने एच-1बी वीजा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए कम से कम 43 आवेदन दिए जबकि लाभ उठाने वाली कंपनी के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोई पद ही नहीं था। आरोपी को वीजा धोखाधड़ी के प्रत्येक आरोप पर 10 साल की कैद और 250,000 डॉलर का अधिकतम जुर्माना तथा मेल धोखाधड़ी के प्रत्येक जुर्म के लिए 20 साल तक की कैद हो सकती है। ।

सऊदी सरकार के सर्वोच्च स्तर पर दिया गया था खशोगी को मारने का आदेश: तुर्की

अंकारा (एजेंसी)।



तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने शुरुवार को कहा कि सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी को मारने का आदेश सऊदी अरब सरकार के सर्वोच्च स्तर से आया था। उन्होंने कहा कि इस हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ है इसका खुलासा करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए ज़रूरी है। वाशिंगटन में ऑप-एंड में एर्दोआन कहते हैं, उन्हें नहीं लगता है कि दो अक्टूबर को सऊदी वाणिज्य दूतावास के भीतर खशोगी को मारने का आदेश सऊदी अरब के शाह सल्मान ने दिया था। वह लिखते हैं कि सऊदी अरब के साथ तुर्की के निकट संबंध हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुर्की एक पत्रकार की मौत पर अपनी आंखें बंद कर लेगा।

एर्दोआन ने कहा, ‘‘हमें पता है कि खशोगी को मारने का आदेश सऊदी अरब सरकार के सर्वोच्च स्तर से

आया था।’’ वह लिखते हैं, ‘‘अंतरराष्ट्रीय समुदाय के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते, खशोगी की मौत के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा करना और सऊदी अरब के अधिकारियों ने किस पर इतना यकीन किया, यह पता करना चाहिए।’’ एर्दोआन यह भी लिखते हैं कि वे लोग हत्या को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस्तांबुल के मुख्य अभियोजक ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिका में निर्वासन में रह रहे खशोगी जैसे ही वाणिज्य दूतावास में घुसे पूर्व नियोजित तरीके से उनका गला घोट दिया गया। फिर उनके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए।

સુરત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ
સુકાભવન, વૈષ્ણવ-અમલવા રોડ, સુરત-૩૬૫૦૦૩
દિપાવલી તથા નૂતન વર્ષ આપના પરિવાર માટે કાનડાથી તેમજ ઉજવવા બંધી રહે તેવી શુભકામનાઓ

> પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત ઉવાડાના મનવીનું સ્વાગત સારક કરીએ
> સુરત શહેર વિકાસમાં ઇસ્પાશન ભરી તત્કાલ વિકાસી રહુ છે અને સુકાનુ કાર્યક્ષેત્ર પણ વિસ્તરેલ છે ત્યારે આપણી આપની મહેનતના નાણા પ્રયોગે મહાન ફરેટ કે કોઈ પણ સ્થાવર મિલકત ખરીદતા પહેલા નીચેની બાબતોની ચકાસણી અવશ્ય કરો

- ◆ રેવન્યુ ટાઈટલ
- ◆ બીનબેન્કીનો કુશળ
- ◆ સુરત મહાનગરપાલિકા- સુકાની વિકાસ પરવાનગી તથા
- ◆ મંજૂર કચેલ પ્લાન પ્રમાણે જ બંધકામ છે તેની ચકાસણી

* યોજાયેલ કાર્યો શહેરી વિકાસ, નિર્મિત થશે ચોક્કસ ઉજાસ *

સુધીર બી.પટેલ, IAS
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

એમ.સેનારસન, IAS
ચેરમેન

કનકપુર-કનસાડ નગરપાલિકા
તા.ચોર્યાસી, જિ.સુરત.

દિવાળી તથા નવા વર્ષના શુભ અવસર નિમિત્તે આપ સૌ નગરજનોને હાર્દિક શુભેચ્છા.

વેરાઓ નિયમિત ભરો
પાણીનો કચરસરપૂર્વક ઉપયોગ કરો
જ્યાં ત્યાં કચરો ફેંકશો નહીં
કચરો ડોર ટુ ડોર ટ્રેક્ટરમાં આપો

લગ્ન નોંધણી અવશ્ય કરાવો
રસતાઓ કે ગલીઓમાં અનઅધિકૃત દબાણ અટકાવો
વૃક્ષોનું જતન કરો
સ્વચ્છતાલક્ષી કાર્યોમાં સહયોગ આપો.

જન્મ-મરણ નોંધણી અવશ્ય કરાવો

(શ્રીમતિ રસાબેન જી. પટેલ) (શ્રી અશ્વિનસિંહ બી. વાલેલા) (શ્રી મહેલભાઈ બી. પટેલ) (શ્રી કે. એમ. કોલવીયા)
પ્રમુખ કારોબારી અધ્યક્ષ ઉપ-પ્રમુખ ચીફ ઓફિસર
કનકપુર-કનસાડ નગરપાલિકા કનકપુર-કનસાડ નગરપાલિકા કનકપુર-કનસાડ નગરપાલિકા કનકપુર-કનસાડ નગરપાલિકા

અન્ય સર્વે સભ્યશ્રીઓ તથા સર્વે કર્મચારીગણ નગરપાલિકા

● SHYAM BHAI

દીપાવી एवं नूतनवर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं...

SHIV SHAKTI SWEETS & SNACKS
The Sweets Shop

RATAN MARKET, RING ROAD,
SURAT. PH : 2363470

Shine with goodness like sparkling lights.
Strive to fulfil your cherished aspirations.
Your good fortune shall bedazzle yourself!
Such is the aura of this festival of lights;
That will bring tons of prosperity and good luck.
With echoes of prayers and gleaming optimism,
Be ready to illuminate new chapters of life.

May God fulfil all your wishes, And bring more mirth, endless love and prosperity in your life.

Happy Diwali

Issued in public interest by Rajhans (Desai-Jain) Group.
Realty | Confectionery | Entertainment | E-commerce | Textile | Hospitality
Surat | Mumbai | Delhi | Pune | Bangalore | Hyderabad | Zurich (Switzerland)
Follow us: [t](#) [i](#) [n](#) [s](#) [e](#) [a](#) [f](#) /RajhansGroupOfIndustries

RAJHANS
DESAI-JAIN GROUP

ધી સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કો.ઓ. બેંક લિ.
સુ. ડિ. કો. એસ
સ્થાપના - ૧૯૭૯

સુ. ડિ. કો. મહાલોન ઉત્સવ - ૨૦૧૮-૧૯
દીવાળી તથા નૂતન વર્ષની હાર્દિક શુભકામનાઓ

કાર લોન **ટુ-વ્હીલર લોન** **હાઉસીંગ લોન** **ડૉક્ટર્સ પ્રોજેક્ટ લોન** **એજ્યુકેશન લોન**
ટ્રેક્ટર લોન **કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ** **સુડીકો ભૂમિપુત્ર યોજના** **સુડીકો ગ્રામલક્ષ્મી કિસાન યોજના** **સિંચાઈ લોન**

ઉપરોક્ત લોન સ્કીમોમાં પ્રવર્તમાન વ્યાજદર અને માર્ગનમાં ખાસ ઘટાડો

- કોઈ ડોક્યુમેન્ટેશન ચાર્જ નહીં.
- કોઈ ઈન્સપેક્શન ચાર્જ નહીં.
- ખેડૂતો માટે ધિરાણની સરળ પદ્ધતિ
- લાંબી મુદત
- કોઈ પાઈ પેમેન્ટ અને ફોર કલોઝર માટે ચાર્જ નહીં
- ઝડપી અપ્રુવલ
- આકર્ષક વ્યાજદર

ચેરમેનશ્રી નરેશભાઈ પટેલ વાઈસ ચેરમેનશ્રી સંદિપભાઈ દેસાઈ

રજી. ઓફિસ : જે. પી. રોડ, અઠવાગેટ, સુરત - ૩૬૫ ૦૦૧ ફોન : ૦૨૬૧-૨૪૬૬૦૦૧, ૨૪૬૬૦૦૨, ૨૪૬૬૦૦૩ Website : www.sudicobank.com

દીપાવલી, નૂતનવર્ષ एवं भाई दुज की हार्दिक शुभकामनाएं.....

એક શુભેચ્છક

"Polio gone Measles is next" "GO For Digital Payment It's Safe & Secure"

સુરત મહાનગરપાલિકા
ખૂબસૂરત સુરતના શહેરીજનોને

શુભ દિપાવલી તથા નૂતન વર્ષાભિનંદન

વિક્રમ સંવત ૨૦૭૪નું વર્ષ વિદાય લઈ રહ્યું છે અને વિક્રમ સંવત ૨૦૭૫ના નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે નવા વર્ષના મંગલમય પ્રારંભે ખૂબસૂરત સુરતના શહેરીજનોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. દિપોત્સવીનું આ પર્વ પ્રત્યેક માનવહૃદયમાં એક વિશિષ્ટ તેજની ઉજાભરી ચેતનાનું સિંચન કરે તથા નૂતન વર્ષ સર્વના માટે સર્વ પ્રકારે મંગલકારી, લાભદાયી અને નિરોગી રહે તેવી અંતરની શુભકામનાઓ...

ડો. જગદીશ પટેલ
મેયર

એમ. થેન્નારસન, IAS
મ્યુ. કમિશનર

નિરવ એસ. શાહ
ડે. મેયર

અનિલ ગોપલાણી
અધ્યક્ષ, સ્વાચી સમિતિ

ગિરિજાશંકર મિશ્રા
નેતા, શાસકપક્ષ

પ્રફુલભાઈ સી. તોગડિયા
નેતા, વિરોધપક્ષ

દક્ષાબેન જરીવાળા
ઈડક, શાસકપક્ષ

સુરત મહાનગરપાલિકાને હેલો સારી રાત્રી

સુરત મહાનગરપાલિકાની મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરો

બી.બી.સી.ઓ./૪૩૩/૨૦૧૮-૧૯ તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૮

જિલ્લા પંચાયત સુરત.

સૌને નૂતન વર્ષાભિનંદન પાઠવે છે.

સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષ દરમિયાન જિલ્લા પંચાયત સુરતે કરેલ સિદ્ધિઓ

- ❖ ૧૪ માં નાણાંપંચની યોજના હેઠળ પ્રથમ હપ્તાની રૂ. ૩૮૦૭.૩૧ લાખની ગ્રાંટ માન. વિકાસ કમિશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર તરફથી મળતાં તમામ ગ્રામ પંચાયતોને ફાળવવામાં આવેલ છે.
- ❖ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના-૨ હેઠળ ૧૧૭૪૨ આવાસોના લક્ષ્યાંક સામે ૧૦૧૦૨ આવાસોનું બાંધકામ કરી ૮૬.૦૩ ટકા સિધ્ધિ હાંસલ કરવામાં આવેલ છે.
- ❖ બાંધકામ ક્ષેત્રે રેતી કાંકરીની ગ્રાંટ હેઠળ કુલ રૂ. ૩૦૦.૦૦ લાખનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. લોકભાગીદારીથી રૂ. ૫.૦૦ કરોડનું આયોજન હાથ ધર્યું. સ્મશાનગૃહમાં ખૂટતી સુવિધા માટે રૂ. ૩૫.૦૦ લાખ ફાળવવામાં આવ્યાં. પ્રવાસન ધામ અંતર્ગત રૂ. ૧૧.૦૦ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા છે.
- ❖ આરોગ્ય ક્ષેત્રે સંસ્થાકીય સુવાવડમાં ખૂબ જ નોંધપાત્ર કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. જનની સુરક્ષા યોજના, ચિરંજીવી યોજના, રસીકરણ, પલ્સ પોલિયો, જિલ્લા પંચાયત સ્વલંડોળમાંથી અસાધ્ય રોગ અંતર્ગત કેન્સર, ક્રીડની મગજની બિમારી જેવા રોગો માટે સહાય આપવામાં આવે છે. મા કાર્ડ યોજના, સીકલસેલ સહાય, લેપ્ટોસ્પાયરોસીસ રોગમાં સહાય આપવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સ્વાઈન ફ્લુ વગેરેમાં ખૂબ નોંધપાત્ર કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.
- ❖ ઈગ્રામ યોજના અન્વયે ૫૭૨ ગ્રામ પંચાયતોને ઈ-કનેક્ટીવીટીથી સાંકળવામાં આવેલ છે. ઈગ્રામ સર્વિસ દ્વારા ગ્રામ પંચાયતમાંથી ખેડૂતોને ગ્રામ પંચાયતોમાંથી ૭-૧૨, ૮-અ, રેલ્વે-બસ ટીકીટ બુકીંગ, ગેસ બીલ, લાઈટ બીલ વગેરે સ્વીકારવામાં આવે છે.
- ❖ શેરડી પાક હેઠળ સુધારેલ બિયારણ માટે જિલ્લા પંચાયત સ્વલંડોળમાંથી સીગલ આઈબડ (શેરડીપાક) માટે રૂ. ૬૦.૦૦ લાખની સહાય અને ૩૦.૦૦ લાખ રોપાઓ આપવાનું આયોજન હાથ ધરેલ છે.
- ❖ શિક્ષણ ક્ષેત્રે - જિલ્લા પંચાયત સ્વલંડોળમાંથી ૩૨ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, ૪૪ પ્રાથમિક શાળાઓની અંદાજીત ૧૧૦૦ મીટર કંપાઉન્ડ વોલ બનાવવા માટે રૂ. ૧.૦૦ કરોડ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીને ફાળવવામાં આવ્યા. ડીઝીટલ ઈન્ડીયાના ભાગરૂપે કુલ ૧૨ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઈ-શિક્ષા શીમ સ્માઈ કલાસની સુવિધા આપવામાં આવનાર છે. ધોરણ ૧ થી ૮ ની શાળાઓમાં કુલ ૧૪૦ લોકર ફાળવેલ છે.
- ❖ સિંચાઈ ક્ષેત્રે પાણીના નવા બોરની રૂ. ૨૦૫.૦૦ લાખની યોજનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કાંઠા વિસ્તારમાં અને અન્ય વિસ્તારમાં રૂ. ૧૫૭.૦૦ લાખનું આયોજન. રેતી-કાંકરી સદર હેઠળ કુલ રૂ. ૬૦.૦૦ લાખનું આયોજન. રીચાર્જીંગના કુલ રૂ. ૫૦.૦૦ લાખના કામોનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે.
- ❖ મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગ (આઈ.સી.ડી.એસ.) - મહિલા અને બાળ કલ્યાણ ક્ષેત્રે પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજનાકેશ ૬૨.૫૭ ટકા લાભાર્થીઓ - સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓને પ્રથમ હપ્તો રૂ. ૧૦૦૦/- દ્વિતીય હપ્તો રૂ. ૨૦૦૦/- તથા ત્રિતીય હપ્તો રૂ. ૫૦૦૦/-ની સહાય આપવામાં આવેલ છે. તેમજ ૦ થી ૫ વર્ષના બાળકો, કિશોરીઓ, સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓને ૧૦૦ ટકા પુરક પોષણ આપવામાં આવેલ છે.
- ❖ પશુપાલન ક્ષેત્રે - પાવર ડ્રીવન ચાફકટર સાધન સહાય યોજના હેઠળ ૧૧ અનુસુચિત જનજાતિ લાભાર્થીઓ, ૬ અનુસુચિત જાતિના લાભાર્થીઓ તથા ૧૨૩ જનરલ કેટેગરીના લાભાર્થીઓની અરજીઓ પૂર્વ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. પાવર ડ્રીવન ચાફકટર યોજનાનું સહાય ધોરણ રૂ. ૧૫,૦૦૦/-.

સ્વરોજગારીના હેતુ પશુપાલન વ્યવસાય માટે ૧૨ કુધાળા પશુના કેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાય યોજના હેઠળ ૭૬ લાભાર્થીઓની અરજીઓ પૂર્વ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના અંતર્ગત સહાય ધોરણ બેંક વ્યાજ સરકારશ્રી દ્વારા ૫ વર્ષ સુધી ચુકવવામાં આવનાર છે.

ડી. કે.પારેખ, IAS
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,
સુરત.

હિતેન્દ્રસિંહ કે. વાંસિયા,
ઉપપ્રમુખ
જિલ્લા પંચાયત સુરત.

પ્રિતીબેન વિ. પટેલ,
પ્રમુખ
જિલ્લા પંચાયત સુરત.